कोविड से छूटे तो नई मुसीबत ने घेरा

■ कार्तिक गणेशन

फेलो एंड रिसर्च कोर्डिनेशन डायरेक्टर, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू)

फरवरी 2022 की शुरुआत में कोविड महामारी धीमी पड़ने के संकेत सामने आए तो भारत और दुनिया के ज्यादातर देशों ने राहत की सांस लेनी शुरू की। लेकिन यह राहत बहुत अल्पायु साबित हुई क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले ने पूरी दुनिया को झटके देने शुरू कर दिए हैं। रूस दुनिया में प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और शीर्ष के तीन पेट्रोलियम उत्पादक देशों में शामिल है। लेकिन यूक्रेन पर क्रूरतापूर्ण हमले के कारण

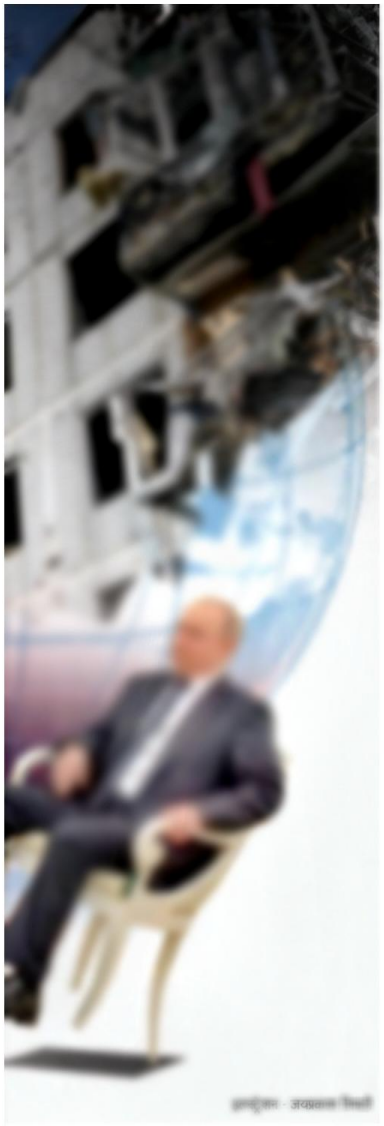

अमेरिका और यूरोप के अधिकांश देशों ने इस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि रूस के साथ वैश्विक व्यापार और साथ में दो प्रमुख ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति में गिरावट आएगी। चूंकि यूरोपीय संघ काफी हद तक रूस से आयातित तेल और गैस पर निर्भर है, जाहिर है कि वे सबसे पहले प्रभावित होंगे। सवाल उठता है कि यह सब भारत को कैसे प्रभावित करेगा?

भारत कच्चे तेल का 85 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा आयात करता है, इसलिए इसकी कीमतों में उछाल का पूरा खमियाजा इसे भुगतना पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें (रुपये के संदर्भ में) लगातार बढ़ रही हैं। मई, 2020 में सबसे निचले स्तर पर पहुंचने के बाद अब यह चौगुनी हो चुकी हैं। अगर यह बढ़ोतरी नहीं होती तब भी महामारी के दौरान खुदरा उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम और अन्य उत्पादों पर कर और शुल्क में काफी ज्यादा बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, 2022 की शुरुआत से जारी कीमत बढ़ोतरी के कारण शुरुआती नवम्बर, 2021 में शुल्कों में दी गई राहत के बेअसर हो जाने की आशंका है।

एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम गैस) कच्चे तेल का एक उत्पाद है, जो भारतीय परिवारों के बीच खासकर शहरी भारत में काफी पसंद किया जाता है। इसकी कीमतों में मई, 2020 से 50 फीसदी बढ़ोतरी देखी गई है। 900 रुपये प्रति एलपीजी रिफिल की वर्तमान कीमत पर औसत भारतीय परिवार के लिए एलपीजी रिफिल का खर्च उसके मासिक खर्च का 7 फीसद से 10 फीसद हो सकता है। इसका उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। उभरते साक्ष्य बताते हैं कि उनमें से कई लोग बीते दो वर्षों में खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन का रुख कर चुके हैं। ऐसे समय में जब खुदरा महंगाई दर ने 6 प्रतिशत के सुविधाजनक स्तर को पार कर लिया है, खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर ऊर्जा कीमतों के कारण आने वाले प्रभावों पर अर्थव्यवस्था के सभी पर्यवेक्षकों की बारीक नजर रहेगी।

भारत की निर्भरता

प्राकृतिक गैस भी एक अन्य ऊर्जा स्रोत है, जिसके लिए भी भारत ज्यादातर आयात पर निर्भर है। वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में प्राकृतिक गैस का आयात घरेलू उत्पादन से ज्यादा हो गया। इसके लिए कुछ हद तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुकूल कीमतें जिम्मेदार रहीं, लेकिन घरेलू उत्पादन में भी ठहराव और यहां तक कि गिरावट के संकेत सामने आए हैं। यह हमारे उर्वरक, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए प्रमुख इनपुट है। शहरी भारत में एलपीजी की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल भी बढ़ाया जा रहा है, और वाहनों में भी स्वच्छ ईंधन के रूप में सीएनजी की प्राथमिकता बढ़ रही है। इन सब के बीच अगस्त, 2021 से यूरोप में गैस की मांग में वृद्धि के कारण वैश्विक स्तर पर इसकी कीमतें दोगुनी से ज्यादा हो चुकी हैं।

बीते छह महीनों में ऑटो रिक्शा, बसों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस के दामों में 15 फीसद की बढ़ोतरी देखी गई है। घरेलू गैस की कीमतों की समीक्षा अप्रैल, 2022 में प्रस्तावित है, इसलिए वैश्विक रुझानों और तेल की कीमत से जुड़े हुए फार्मूले को देखते हुए इसके दाम में निश्चित तौर पर एक और बढ़ोतरी की उम्मीद है।

चूंकि गैस और तेल के ज्यादातर हिस्से का आयात किया जाता है, ऐसे में भारत कोयले की तरफ रुख कर सकता है क्योंकि यह घरेलू स्तर पर उपलब्ध है। अपने इस्तेमाल में यह बिजली उत्पादन और उद्योगों के लिए पहले से तैयार विकल्प है, इसलिए यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल करने की छूट दे सकता है। हालांकि, अक्टूबर, 2019 से कोयले की मांग सुस्त बनी हुई है। बावजूद इसके 2021 में मानसून के बाद के सीजन में हमने कोयले की आपूर्ति में कमी और इसकी अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल को देखा था। इसने कम से कम इस दशक में कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने की हमारी क्षमता को सवालों के घेरे में ला दिया है। फिर भी रूस के आक्रमण के बाद से कोल इंडिया के शेयर की कीमतों में दिखा उछाल भविष्य में ऊंची कीमत वाली व्यवस्था विशेष रूप से विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए ई-नीलामी में सामने आने का संकेतक है। ठीक इसी तरह यह इस बात का भी संकेत है कि अनिश्चितता के इस दौर में कोयला ज्यादा मूल्यवान संसाधन है।

इन परिस्थितियों ने भले ही भारत के लिए ऊर्जा की कीमतों और आपूर्ति के लिए चिंताजनक तस्वीर पेश की है, लेकिन इसने समान रूप से उस गति को बढ़ाने का अवसर भी दिया है, जहां हम अपनी जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा व्यवस्था के विकल्पों की योजना बनाते और उसे जमीन पर उतारते हैं। कोयले के उपयोग में कुशलता को प्राथमिकता देना और अकुशल उत्पादन वाली परिसंपत्तियों (पॉवर प्लांट्स) को हटाना अच्छी शुरुआत होगी। घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग भी इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की संभावनाओं के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भी सही समय पर घोषित किया गया है। यह हमारी औद्योगिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। कुल मिलाकर यह देश के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छ हवा, घरेलू उद्योग को प्राथमिकता देने और अंततः भारत को ऊर्जा सुरक्षा का आभास कराने का सही समय है, जो हमेशा से ही पकड़ से बाहर रहा है।

(सीईईडब्ल्यू स्वतंत्र गैर-लाभकारी नीति शोध संस्थान है)

■